प्रेस विज्ञप्ति

रांची, झारखंड | 19 सितंबर, 2022

iFOREST ने सामाजिक-आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण झारखंड में DRE निवेश के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड को अनलॉक करने पर अध्ययन जारी किया

•iFOREST ने रांची में 'ग्रामीण झारखंड में सामाजिक बुनियादी ढांचे और आजीविका के लिए स्वच्छ ऊर्जा को सक्षम करने के लिए DMF फंड अनलॉकिंग' पर एक रिपोर्ट जारी की।
•पांच शीर्ष खनन जिलों में ऊर्जा जरूरतों का आकलन लगातार विद्युतीकरण और बिजली आपूर्ति अंतराल, और सेवाओं की गुणवत्ता और उत्पादकता पर इसके प्रभाव को उजागर करता है।
• सौरीकरण तत्काल ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक तकनीकी और वित्तीय रूप से प्रभावी समाधान प्रदान करता है; इसे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
• डीएमएफ फंड धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका उपयोग जिले सामाजिक बुनियादी ढांचे के सौरकरण के लिए कर सकते हैं - स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र; और आजीविका क्षेत्र। इससे विकास संकेतकों में सुधार होगा और रोजगार भी पैदा होंगे।
• झारखंड के खनन जिले एक व्यापक 'सामाजिक बुनियादी ढांचे और आजीविका के लिए स्वच्छ ऊर्जा' कार्यक्रम को डिजाइन और कार्यान्वित कर सकते हैं जो जिलों के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, स्वच्छ ऊर्जा विकास का समर्थन कर सकता है और साथ ही ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार पैदा कर सकता है।

रांची, झारखंड: इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (iFOREST) ने सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मौजूदा सामाजिक बुनियादी ढांचे और आजीविका क्षेत्रों में वितरित अक्षय ऊर्जा (DRE) के एकीकरण की योजना बनाने में झारखंड के प्रमुख खनन जिलों का समर्थन करने के लिए अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है जिसका उदेश्य उत्पादकता और संचालन की मापनीयता बढ़ाने की ओर है।
अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के फंड का इस्तेमाल इसका समर्थन करने के लिए किया जा सकता है।

खनन प्रभावित समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए काम करने के लिए हर खनन जिले में डीएमएफ ट्रस्ट हैं। डीएमएफ का पैसा जिलों में संचालित खनन कंपनियों द्वारा भुगतान से आता है। वर्तमान में झारखंड में डीएमएफटी में रु. 8,600 करोड़ हैं, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।

iFOREST रिपोर्ट बताती है कि लगातार विद्युतीकरण अंतराल और परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में बिजली की मौलिक भूमिका के कारण, जिले के सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे में ऊर्जा को एकीकृत करने को DMF खर्च के तहत प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डीएमएफ, स्थानीय रूप से जमीनी निकाय होने के नाते, एक प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद कर सकता है जो दूरस्थ स्थानों में डीआरई निवेश की स्थिरता सुनिश्चित करता है।

रिपोर्ट का विमोचन रांची में श्री बिष्णु सी परिदा, मुख्य संचालन अधिकारी, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी और सुश्री नैंसी सहाय (आईएएस), डिप्टी कलेक्टर, हजारीबाग, झारखंड सरकार की आभासी उपस्थिति में किया गया। चर्चा बैठक में डीएमएफ प्रतिनिधियों, नागरिक समाज, सौर ऊर्जा डेवलपर्स, डीआरई निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य विशेषज्ञों सहित एक बहु-हितधारक समूह ने भाग लिया।

iFOREST ने झारखंड के पांच खनन जिलों - चतरा, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम पर केंद्रित एक संकेतक ऊर्जा जरूरतों के आकलन अध्ययन पर अपनी सिफारिश पर आधारित है। ये जिले सामूहिक रूप से झारखंड के कुल डीएमएफ उपार्जन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा हैं, और जहां व्यापक बहुआयामी गरीबी है।

“हमने पांच जिलों में विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, किसानों, कृषि-आधारित सूक्ष्म उद्यमों और पंचायतों के प्रतिनिधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 258 साक्षात्कार आयोजित किए, ताकि वर्तमान बिजली आपूर्ति की स्थिति, DRE एप्लिकेशन, प्रमुख बिजली-निर्भर आवश्यकताओं और मौजूदा अनुभव का आकलन किया जा सके, ” मांडवी सिंह, प्रोग्राम लीड, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, iFOREST और शोध रिपोर्ट के प्रमुख लेखक।

उसने समझाया “यह स्पष्ट है कि विद्युतीकरण और बिजली आपूर्ति की कमी है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण केंद्रों में प्रकाश, शीतलन और पानी की उपलब्धता की बुनियादी चुनौतियों का कारण बन रही है, जिससे संचालन मुश्किल हो जाता है और कई बार अव्यवहारिक हो जाता है। सेवाओं की गुणवत्ता और

उत्पादकता में सुधार के लिए बेहतर बिजली आपूर्ति की संभावना पर एक स्पष्ट सर्वसम्मति उभर रही है।"

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री बिष्णु सी परिदा, मुख्य परिचालन अधिकारी, जेएसएलपीएस ने कहा: डीएमएफ डीआरई खर्च को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि समाधानों की उचित डिजाइनिंग के माध्यम से इन परिसंपत्तियों का अनुकूलन किया जाए।

डीआरई समाधान जैसे सौर छत, सिंचाई और पीने के पानी के लिए सौर जल पंप, मिनीग्रिड आदि पहले से ही ग्रामीण झारखंड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनकी तैनाती को कई गुना बढ़ाने की जरूरत है। सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित गैर-लाभकारी ट्रस्ट के रूप में डीएमएफ को आदर्श रूप से महत्वपूर्ण सामाजिक बुनियादी ढांचे और आजीविका क्षेत्रों के सौरकरण की दिशा में निवेश जुटाने के लिए रखा गया है।

आईफोरेट में जस्ट ट्रांजिशन की निदेशक डॉ श्रेष्ठ बनर्जी ने समझाया, "हालांकि 'ऊर्जा' वर्तमान में डीएमएफ खर्च के लिए एक 'अन्य प्राथमिकता क्षेत्र' है, यह कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश का महत्वपूर्ण पूरक है और सेवा वितरण में सुधार कर रहा है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बाल विकास, आजीविका शामिल है, जो खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। डीएमएफ इन क्षेत्रों को डीआरई के माध्यम से कवर करने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपना सकते हैं। यह उस पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने में भी मदद करेगा जो लागत में कमी का समर्थन करता है। यह सौर निवेश और हरित नौकरियों के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा, जो एक ऊर्जा संक्रमण के लिए भी महत्वपूर्ण है।"

सुश्री नैन्सी सहाय (आईएएस), डिप्टी कलेक्टर, हजारीबाग, झारखंड सरकार ने कहा : डीआरई में निवेश करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि बिजली की आपूर्ति एक बड़ी समस्या रही है। यह आवश्यक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने से सरकारी तंत्र की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। लेकिन एकीकरण के लिए एसओपी लागू करने पर स्पष्टता जरूरी है।"

iFOREST की रिपोर्ट से पता चलता है कि DMF को सामाजिक बुनियादी ढांचे और आजीविका (CESIL) कार्यक्रम के लिए एक व्यापक स्वच्छ ऊर्जा की योजना बनानी चाहिए और उसे रोल आउट करना चाहिए, जिसका लक्ष्य 100 सौर गाँव स्थापित करना, सभी स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा केंद्रों को सोलराइज़ करना, 1,000 ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों को भी तैनात करना, क्षमता निर्माण और बीज वित्त पोषण सहायता प्रदान करके 150 सौर उद्यमियों का निर्माण करना है। । इस कार्यक्रम से पूरी तरह से प्रत्येक जिले में 12 मेगावाट से 18 मेगावाट सौर क्षमता के बीच पर्याप्त सौर क्षमता वृद्धि होगी। निवेश

की आवश्यकता 94 करोड़ रुपये से लेकर 132 करोड़ रुपये तक होगी, जो प्रत्येक प्रमुख खनन जिलों में डीएमएफ संचय का केवल एक छोटा सा घटक है।

सांकेतिक ऊर्जा मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष है:

• सामाजिक-बुनियादी ढांचे के मामले में, यादृच्छिक रूप से सर्वेक्षण किए गए लगभग 36 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों, 23 प्रतिशत स्वास्थ्य केंद्रों और 20 प्रतिशत स्कूलों में दौरे के समय ग्रिड-कनेक्शन या सक्रिय कनेक्शन की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में औसत दैनिक बिजली आपूर्ति 6-18 घंटे के बीच बताई गई। अधिकांश केंद्रों ने बिजली आपूर्ति परिदृश्य के कारण नियमित परिचालन चुनौतियों का सामना करने की सूचना दी। चतरा, धनबाद और पश्चिमी सिंहभूम में विद्युतीकरण और आपूर्ति अंतराल अधिक देखा गया, जिनमें डीएमएफ फंड का सबसे अधिक हिस्सा है।

• कृषि में, लगभग 80 प्रतिशत भूमि अभी भी वर्षा पर निर्भर है और कृषि फीडर की पहुंच कमजोर बनी हुई है। सर्वेक्षण किए गए किसानों का उपयोग करने वाले लगभग 60 प्रतिशत बिजली पंप एकल-चरण ग्राम फीडर लाइन पर निर्भर थे, जो बड़ी आपूर्ति अनियमितताओं और वोल्टेज के मुद्दों से ग्रस्त हैं। सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक किसान डीजल पर निर्भर थे, और मुख्य रूप से ईंधन की बढ़ती लागत के बारे में चिंतित थे।

• कृषि आधारित सूक्ष्म उद्यमों के मामले में, सर्वेक्षण में शामिल 91 प्रतिशत व्यवसायों के पास ग्रिड कनेक्शन था, जबकि केवल 40 प्रतिशत संचालन के लिए ग्रिड आपूर्ति पर निर्भर थे। ये बड़े पैमाने पर सूक्ष्म पैमाने पर मुर्गी पालन और न्यूनतम बिजली निर्भरता वाली डेयरी इकाइयां थीं। हालांकि, लगभग सभी पीसना, हलिंग, प्रसंस्करण और मत्स्य संबंधी व्यवसाय डीजल से चलने वाली मोटरों का उपयोग कर रहे थे और ईंधन की बढ़ती लागत के बारे में चिंतित थे।

iForest के बारे में:

इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (iFOREST) एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी पर्यावरण अनुसंधान और नवाचार संगठन है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के एक समूह द्वारा स्थापित, यह कुछ सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरण-विकास चुनौतियों के समाधान खोजने, बढ़ावा देने और स्केल-अप करने का प्रयास करता है। यह महत्वपूर्ण मुद्दों और कार्यक्रमों में नागरिकों को सूचित और संलग्न करके पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास करता

है। iFOREST राज्य में डीएमएफ कार्यान्वयन के लिए खान मंत्रालय, झारखंड को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।